भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2680
(05 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली

2680. श्री संजय उत्तमराव देशमुखः
श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली सहित विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, विशेषकर महाराष्ट्र के बीड लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का ग्राम-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ख): ग्रामीण विकास मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) , दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) , दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयूजीकेवाई) , ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) एवं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) जैसी कई कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है।

इन योजनाओं/कार्यक्रमों का उद्देश्य गरीबी को कम करना तथा आजीविका के अवसरों को मजबूत बनाते हुए , न्यूनतम गारंटीकृत रोजगार प्रदान करके , स्व-रोजगार को बढ़ावा देकर , विभिन्न उपयोगी व्यवसायों और उद्यमिता गुणों में युवाओं को कुशल बनाकर, अवसंरचनात्मक विकास करके और सामाजिक सहायता का प्रावधान करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में समग्र सुधार लाना है।

इसके अतिरिक्त, पीएमएवाई-जी के तहत महाराष्ट्र के बीड लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित देश भर के सभी पात्र गांवों के लाभार्थियों के लिए अभिसरण के माध्यम से आवास के अलावा , पाइप पेयजल, शौचालय, बिजली कनेक्शन, एलपीजी गैस कनेक्शन, सौर लालटेन, खाना पकाने की स्वच्छ ऊर्जा और सौर छत जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाती हैं।

इसके अतिरिक्त, जहां तक ग्रामीण परिवारों को बिजली आपूर्ति का प्रश्न है , विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने हमेशा दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) , एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) , प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) आदि योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों की पूर्ति की है , ताकि महाराष्ट्र के बीड लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित सभी परिवारों को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में उनकी सहायता की जा सके।

भारत सरकार जुलाई, 2021 में शुरू की गई पुनरोद्धार वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) की चल रही योजना के तहत , सौभाग्य के दौरान छूटे हुए घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए राज्यों को अतिरिक्त सहायता प्रदान कर रही है। इसके अलावा , पीएम जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान) के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) से संबंधित सभी चिन्हित घरों और डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के तहत जनजातीय परिवारों को योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार आरडीएसएस के तहत ऑन-ग्रिड बिजली कनेक्शन के लिए मंजूरी दी जा रही है।

****